वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
मंत्रिमंडल के लिए अगस्त, 2021 माह हेतु मासिक सारांश

अगस्त, 2021 माह के दौरान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां और महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में एक अद्यतन रिपोर्ट (अपडेट) निम्नवत है:-

1. जुलाई, 2021 माह के लिए 5,95,137.99 करोड़ रुपये के कैपेक्स लक्ष्य और चुनिंदा सीपीएसईज़ और अन्य संगठनों के 1,33,762.14 करोड़ रुपये की इसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी 5 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई है।
2. वर्ष 2021-22 के लिए सीपीएसई के एमओयू के लिए सेक्टोरल बेंचमार्किंग पर माह के दौरान 11 बैठकों का आयोजन किया गया था ।
3. टिप्पणियों के लिए प्राप्त अन्य मंत्रालयों/विभागों के तीन मसौदा कैबिनेट/एसएफसी नोटों की डीपीई द्वारा जांच की गई और माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए व्यय विभाग को टिप्पणियां भेजी गईं।
4. माह के दौरान 12 आईएमजी/सीजीडी/पीपीपीएसी/सीएमसीडीसी की बैठकें आयोजित की गईं।
5. निम्नलिखित पदों को तत्काल आमेलन के नियम से छूट दी गई थी:

i. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में बोर्ड स्तर से नीचे के 95 पदों को (75 तकनीकी और 20 गैर-तकनीकी) तीन वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः 31.05.2021 और 29.12.2023 तक ।

ii. कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बोर्ड स्तर से नीचे के 28 पद दिनांक 12.01.2021 से 3 वर्ष की अवधि के लिए।

6. डीपीई तथा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने सीपीएसईज़ के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दिनांक 13 अगस्त, 2021 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का संयुक्त रूप से आयोजन किया।
7. डीपीई ने डेटा हब के रूप में जीआईएफटी-आईएफएससी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति पर उन्हें जागरूक बनाने के लिए दिनांक 4 अगस्त, 2021 को (बीवीसी मोड के माध्यम से) महारत्न, नवरत्न और रेलवे सीपीएसईज़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आर्थिक कार्य विभाग और जीआईएफटी-आईएफएससी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
8. निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया और सहमति बनी:-

i. लोक उद्यम चयन बोर्ड के परामर्श से अध्यक्ष, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जेसीआई) और प्रबंध निदेशक, जेसीआई के पद का विलय अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक, जेसीआई के रूप में करने के लिए वस्त्र मंत्रालय का प्रस्ताव।

ii. लोक उद्यम चयन बोर्ड के परामर्श से कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (व्यवसाय विकास) के पद के सृजन के लिए कोयला मंत्रालय का प्रस्ताव।

iii. केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के माध्यम से सीएमडी, एनएमडीएफसी के पद को भरने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रस्ताव।

9. डीपीई ने दिनांक 02.08.2021 और 03.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 2017, 2007, 1997, 1992 और 1987 के आईडीए वेतनमानों के लिए 01.07.2021 से प्रभावी मंहगाई भत्ता आदेश जारी किए, जिससे पीएसई कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता बढ़ गया। इसी प्रकार सीपीएसई के कर्मचारियों के लिए 5वें और 6ठे सीपीसी सिफारिशों के अनुसार सीडीए वेतनमान का अनुपालन करते हुए डीए के संशोधन के आदेश जारी किए गए थे।

10. केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसई) को मकान किराया भत्ता (एचआरए) प्रदान करने के उद्देश्य से मथुरा-वृंदावन नगर निगम को 'वाई' श्रेणी के शहर के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए दिनांक 25.08.2021 को दिशानिर्देश जारी किया गया था।
11. सीपीएसईज़ के कार्य-निष्पादन को दर्शाने वाली वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लोक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट 6 अगस्त, 2021 को लोकसभा में और 9 अगस्त, 2021 को राज्यसभा में प्रस्तुत की गई।
12. वित्त मंत्रालय के दिनांक 17.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(1) एफएससीसी/2021 के आदेश के अनुसार, डीपीई को गैर-रणनीतिक क्षेत्र के संबंध में नई सीपीएसई नीति को लागू करने का कार्य सौंपा गया था।
13. डीपीई को सीपीएसईज़ के परिसंपत्ति मुद्रीकरण/भूमि मुद्रीकरण का कार्य भी सौंपा गया था।
14. डीएआरपीजी के सुझावों के अनुरूप फाइलों को प्रस्तुत करने के चैनल को अधिकतम तीन/चार स्तरों तक सीमित करने के लिए डीपीई में अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य आवंटन को पुनर्व्यवस्थित किया गया था।

****